शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य और उपलब्धि निम्न प्रकार रही है :–

	शौचालयों की संख्या		
वर्ष	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के अंतर्गत संयुक्त लक्ष्य	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1991–92	341954	184957	54.08
1992–93	340915	328073	96.23
1993–94	499975	293701	57.74
कुल :	1182844	806731	68.20

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि राज्यों की स्वास्थ्य शिक्षा और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों की निगरानी के लिये स्वच्छता प्रकोष्ठ बनाने की सलाह दी गई है। केन्द्रीय स्तर पर भी निगरानी को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

510. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को हाल ही में यह चेतावनी दी गई है कि वे जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवंटित राशि का अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग न करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच भी है कि गत वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1992–93 की अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि जवाहर रोजगार योजना सहित अनेक योजनाएं अपेक्षित रूप में लाभकारी सिद्ध नहीं हुई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रभावी निगरानी व्यवस्था कायम करने पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) यह सच है कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित निधियों का अन्य प्रयोजनों पर इस्तेमाल न करें।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1992–93 की अपनी रिपोर्ट में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं किया है कि जवाहर

रोजगार योजना अपेक्षित रूप से लाभकारी नहीं रही है। वास्तव में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा मासिक, तिमाही और वार्षिक रिपोर्टों की मार्फत नियमित निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य मुख्यालय, जिला, उप मण्डल तथा खण्ड स्तर के अधिकारी कार्य स्थलों का दौरा करके कार्यक्रम के सभी पहलुओं की गहन निगरानी करते हैं। प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विकास हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति भी इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में भाग लेता है।

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 1993 के दौरान क्षेत्र अधिकारियों की एक योजना भी आरम्भ की है। इस योजना के अंतर्गत उप सचिव और उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों को, प्रत्येक को एक अथवा दो राज्य आंटे गये हैं। उन अधिकारियों को उन्हें आबंटित राज्य/राज्यों का दौरा करना होता है और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी देनी होती है। ग्रामीण गरीबों और बेरोजगारों के अधिक अनुपात वाले राज्यों की ओर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से पहली जनवरी, 1994 से क्षेत्र अधिकारी योजना को, इसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बंजर भूमि विकास विभाग योजना आयोग के अधिकारियों को भी शामिल करके और सुदृढ़ बनाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Programmes for Rural Development by Voluntary Agencies

511. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI RAM CHANDRA PILLAI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the programmes which are being executed through the voluntary agencies;
(b) the expenditure incurred in such programmes in the last three years, Statewise; and

(c) the names of the voluntary agencies involved, indicating the amount of finances executed by each of them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) Voluntary agencies are funded projects through Council for advancement of people's Action and Rural Technology (CAPART) by the Ministry of Rural Development covering areas of Jawahar Rojgar Yojana (JRY), Integrated Rural Development Programme (IRDP), Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA), Public Cooperation (PC), Oranisation of Beneficiaries (OB), Advancement of Rural Technology Scheme (ARTS), Central Rural Sanitation Programmes (CRSP) and Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP).

(b) and (c) A statement giving Statewise details of number of projects sanctioned, number of voluntary agencies assisted, amount sanctioned and amount released by CAPART during the last years is at Annexure. [*See* Appendex 171., Annexure No. 14].

Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission

512. SHRI GAYA SINGH: Will the PRIME MINISER be pleased to state:

(a) whether any assessment is made of the progress of the work on providing to